**भारत सरकार**
**महिला एवं बाल विकास मंत्रालय**
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या 2210**
दिनांक 12 दिसम्बर, 2025 को उत्तर देने के लिए

## प्रमुख महिला योजनाओं का कार्यान्वयन

**2210. श्री के. राधाकृष्णन:**

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में पोषण अभियान, वन स्टॉप सेंटर और बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ जैसी प्रमुख योजनाओं के कार्यान्वयन में विलंब/अंतराल की जानकारी है;
(ख) इन योजनाओं के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान आबंटित निधि के मंद उपयोग के कारणों का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या इन कार्यक्रमों के प्रभाव का आंकलन करने के लिए कोई स्वतंत्र आकलन किया गया है; और
(घ) यदि हाँ, तो महिलाओं और बच्चों और विशेषकर ग्रामीण और सीमांत समुदायों के सेवाओं की प्रभावी प्रदायगी सुनिश्चित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**
**महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री**
**(श्रीमती सावित्री ठाकुर)**

**(क) से (घ):** सरकार सभी महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, संरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण तथा सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और उनका शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया गया है।

पोषण अभियान (पूर्ववर्ती राष्ट्रीय पोषण मिशन) मार्च 2018 में शुरू किया गया था। 15वें वित्त आयोग के तहत, कुपोषण की चुनौतियों के समाधान के लिए **सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0** नामक व्यापक मिशन (मिशन पोषण 2.0) के तहत आंगनवाड़ी सेवाओं, पोषण अभियान

और किशोरियों के लिए योजना (आकांक्षी जिलों और पूर्वोत्तर क्षेत्र में 14-18 वर्ष की) जैसे विभिन्न घटकों को मिला दिया गया है। इस मिशन के तहत योजनाएं सार्वभौमिक और स्वयं-चयन की हैं, जहां किसी भी लाभार्थी के लिए पंजीकरण करने और मुफ्त सेवाएं प्राप्त करने के लिए कोई बाधा नहीं है।

**व्यापक मिशन शक्ति के तहत** वन स्टॉप सेंटर संबल वर्टिकल का एक घटक है। यह निजी और सार्वजनिक दोनों स्थानों पर हिंसा से प्रभावित और संकटग्रस्त महिलाओं को एक ही स्थान पर एकीकृत और तत्काल सहायता तथा सहयोग प्रदान करता है। यह जरूरतमंद महिलाओं को चिकित्सा सहायता, कानूनी सहायता और सलाह, अस्थायी आश्रय, पुलिस सहायता और मनो-सामाजिक परामर्श जैसी सेवाएं प्रदान करता है।

**व्यापक मिशन शक्ति के तहत** बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भी संबल वर्टिकल का एक घटक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना घटते बाल लिंग अनुपात में सुधार लाने तथा बालिकाओं और महिलाओं के सशक्तीकरण से संबंधित मुद्दे के समाधान में मदद करने के लिए 22 जनवरी 2015 को शुरू की गई थी। इस योजना में विभिन्न हितधारकों को सूचित, प्रभावित, प्रेरित, शामिल और सशक्त बनाकर बालिकाओं के प्रति मानसिकता और व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है।

मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 तथा मिशन शक्ति केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं और इन योजनाओं के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) की एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) अथवा एसएनए स्पर्श के लिए निर्धारित व्यय विभाग के दिशा-निर्देशों के आधार पर निधियां जारी की रही हैं।

इसके अलावा, वर्ष में एक बार कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड (पीएबी)/वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (एपीआईपी) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ इस योजना के अंतर्गत कार्यकलापों की प्रगति की निगरानी करता है और उद्देश्यों की प्राप्ति की स्थिति, ग्रामीण और वंचित समुदायों सहित महिलाओं और बच्चों को सेवाओं की प्रभावी प्रदायगी की समीक्षा करता है। इसके अलावा, मंत्रालय के अधिकारी बैठकों, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंगऔर समय-समय पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के क्षेत्र दौरे के माध्यम से इस योजना की लगातार समीक्षा करते हैं।

नीति आयोग ने वित्तीय वर्ष 2019 से 2024 के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की योजनाओं का मूल्यांकन किया है। इस अध्ययन में पाया गया कि वन स्टॉप सेंटर तथा बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अत्यधिक प्रासंगिक योजनाएं हैं और एकीकृत, डेटा-संचालित सेवाओं के माध्यम से प्रमुख लैंगिक चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान करती हैं। कमजोर समूहों को प्राथमिकता देकर और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देकर, यह पहल देश भर में महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण को मजबूत करती है। पोषण अभियान के संबंध में, इस अध्ययन में पाया गया कि देश में कुपोषण से निपटने के लिए इसकी प्रासंगिकता संतोषजनक है।

***